



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट—<http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाषनं. — 0755-2466970, 2466859

फैक्सनं. — 0755-2462136

No: 254/ SEIAA/2025

Date: 23/05/2025

प्रति,

M/s The MP State Mining Corporation Limited,
Shri Dammu Raikwar, Authorized Person,
Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor,
Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011
E-mail - pannampsmcl@gmail.com

विषय :- Proposal No. SIA/MP/MIN/518798/2025- Case No. P2/257/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 5.50 ha for production Capacity of 26400 cum per year, Khasra No. 605, Village – Udla, Tehsil - Amanganj, District - Panna (M.P.) by M/s The MP State Mining Corporation Limited, Shri Dammu Raikwar, Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011.

विषयान्तर्गत प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 776वीं बैठक दिनांक 22.02.2025 में पर्यावरण अनुमति प्रदान न किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण दिनांक 07.03.2025 को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को अग्रेषित किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण SEIAA की बैठक में विचारण नहीं होने के कारण 45 दिवस से अधिक की अवधि समाप्त हो गई है।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के पैरा 8 की कंडिका (iii) इस प्रकार है - "In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in subparagraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned."

अतः ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार उक्त प्रकरण में SEAC की 776वीं बैठक दिनांक 22.02.2025 में पर्यावरण स्वीकृति नहीं दिये जाने हेतु की गई अनुशंसा को अंतिम निर्णय मानते हुए राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा "Deemed Approval" माना जाकर पर्यावरण अनुमति नहीं दी जाती है। तदनुसार प्रकरण में ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार आगामी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आप स्वतंत्र हैं।

(प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमोदित)

(श्रीमन् शुक्ला)

कार्यपालन संचालक, एण्डो
एवं सदस्य सचिव, SEIAA

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
4. अध्यक्ष, SEIAA, एप्को पर्यावरण परिसर भोपाल (म.प्र.)।
5. अध्यक्ष SEAC, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)।
6. सदस्य सचिव, SEAC एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल।
7. कलेक्टर, जिला पन्ना (म.प्र.)।
8. वन मंडलाधिकारी, जिला पन्ना (म.प्र.)।
9. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
10. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
11. खनिज अधिकारी, जिला पन्ना (म.प्र.)।
12. संबंधित फाईल।

की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन संचालक, एप्को
एवं सदस्य सचिव, SEIAA

21. **Case No P2/257/2024, Shri Dammu Raikwar, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block - A, 2 nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)- (EIA). Sand Mine in area of 5.50 Hectare, Khasra No.- 605 in Village – Udla, Tehsil - Amanganj, District - Panna (MP), Maximum Production – 26,400 cum per annum [518798]**

The case is presented by the Environmental Consultant Shri MD Mahmood Ghouse, M/s. AmplEnviron Pvt. Ltd., Hyderabad along with PP Shri Dammu Raikar, MPSMCL. (Authorized Person) along with Mining Officer Shri Ravi Patel.

PP submitted following details on Parivesh Portal:

Project details	Information submitted by PP on the Parivesh portal	
Name of Project Proponent / Name of Company/ Institute	Shri Dammu Raikwar, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) जिला कार्यालय, पन्ना MPSMCL, Paryawas Bhawan, Block No. 1-A, 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal (M.P) - 462011. Prior Environment Clearance for Udla River Sand Quarry with a Production Capacity of 26,400 m ³ /year having a lease area of 5.500 Ha., at Khasra No.- 605 in Village - Udla, Tehsil - Amanganj, District – Panna (M.P.). For-EIA Presentation. <u>SIA/MP/MIN/518798/2024</u>	
Khasra No. / Lease Area / Category of the project	Khasra No. 605	Area in 5.500 Ha. Category of the project -B-1
TOR status on Parivesh Portal	Auto TOR granted on dated 29.02.2024	
Name of River	Sand mining is proposed on Ken River	
Lease status according to available Google Image	PP submitted that : No Road bridge / stop dam / railway track is existing in the lease area. Road Bridge is present at 0.01km (NNW) in Upstream Direction.	
Ekal Certificate Details	No	
Gram Panchayat NOC	No adverse comments have been given in the Gram Panchayat NOC.	

Lease status in the District Survey Report (DSR).	PP submitted the lease details are mentioned in the DSR's Page no. <u>21</u> Sr. no. <u>21</u> .
Public Hearing issues	Public Hearing issues / objections/ suggestions raised during Public Hearing meeting are addressed properly in the EMP and in the CER proposal.
Name of Environmental Consultant	Environmental Consultant Shri <u>MD Mahmood Ghouse</u> , <u>M/s. AmplEnviron Pvt. Ltd.</u> , (AEPL). Firm's Validity up to <u>28-12-2026</u>

During presentation it was observed by the committee that the NH-43 road bridge is situated at distance of 05 meter. Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2016 & 2020 के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2016 एवं 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बैक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

Hence, Committee decided that the can not be considered for EC in the light of Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2016 & 2020